धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, राजस्थान ग्लोबल टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनेगा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में केबिनेट ने व्यापार, निवेश व प्रशासनिक सुधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये

जयपुर, 3 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की प्रशासनिक सुगमता, निवेश वृद्धि, व्यापार विस्तार और पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने "ईज ऑफ लिविंग" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 11 अधिनियमों में मामूली उल्लंघनों पर लागू कारावास के प्रावधान हटाकर केवल अर्थदंड का विकल्प रखा जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि वन भूमि में मवेशी चराने या दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे छोटे अपराधों पर अब जेल की सजा नहीं होगी। जयपुर वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम में भी जल बर्बादी अथवा सीवरलाइन में बिना अनुमति कनेक्शन जोड़ने पर कारावास के स्थान पर केवल जुर्माने का प्रावधान रहेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी नीति-2025 (एनआरआर पॉलिसी) को मंजूरी दी गई है। इस नीति के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के निवेश, ज्ञान-साझेदारी, शोध, उद्यमिता और सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा दिया जाएगा।

व्यापार और छोटे दुकानदारों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी दी है।

राज्य में पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से राजस्थान पर्यटन नीति-2025 को भी हरी झंडी दी गई। इसमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, धार्मिक पर्यटन मार्गों का निर्माण, वन एवं धार्मिक क्षेत्रों के पास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, बर्ड वॉचिंग सर्किट, प्रोजेक्शन मैपिंग, ई-व्हीकल टूर, राजस्थान ट्रैवल कार्ड, होम-स्टे और पेइंग गेस्ट सुविधाओं को बढ़ावा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिये 15 एकड़ भूमि निशुल्क दी जायेगी, ताकि बड़े विमानों का आवागमन सुचारु रुप से हो सके।
- ग्यारह अधिनियमों में मामूली उल्लंघनों पर लागू कारावास के प्रावधान को हटा कर केवल अर्थदंड का विकल्प रखा गया है। इससे मुकदमेबाजी में कमी आयेगी।

रूसी संसद ड्यूमा ने भारत-रूस सैन्य समझौते को मंजूरी दी

मास्को, (वार्ता)। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने मंगलवार को भारत के साथ एक प्रमुख अंतर-सरकारी समझौते को मंजूरी प्रदान की,

- रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पूर्व मिली मंजूरी से स्पष्ट है कि दोनों देशों में सैन्य समझौता लगभग फाइनल है।

जिसमें एक-दूसरे के क्षेत्र में सैन्य कर्मियों के साथ-साथ सैन्य जहाजों एवं विमानों को भेजने की प्रक्रिया शामिल है। यह रसद समझौता 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चार दिसंबर से शुरू हो रही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नयी दिल्ली की राजकीय यात्रा से पहले रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तास एजेंसी ने कहा कि समझौते में, "रूस की सैन्य इकाइयों, नौसैनिक जहाजों एवं सैन्य विमानों को भारतीय क्षेत्र में भेजने की प्रक्रियाओं पर रूसी सरकार एवं भारत सरकार के बीच समझौता और भारत की सैन्य इकाइयों, नौसैनिक जहाजों और सैन्य विमानों को रूसी क्षेत्र में भेजने और उनके पारस्परिक सैन्य समर्थन पर 18 फरवरी, 2025 को मास्को में हस्ताक्षिरत समझौते की पुष्टि की जाएगी।"

देने जैसे अनेक प्रावधान शामिल हैं।

इसके साथ ही किशनगढ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 15 एकड अतिरिक्त भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे बडे विमानों के संचालन हेतु आवश्यक एप्रोच लाइट्स की स्थापना संभव हो सकेगी। इससे कोहरे और रात्रि के समय भी सुरक्षित उडान संचालन के साथ पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया के बड़े देशों की नज़र है

एस-400 और एस-500 खरीद सहित ऑयल डील पर चर्चा होगी

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा पर गुरुवार को दिल्ली आ रहे हैं. उनकी यह यात्रा कई मायनों में खास होगी. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरु होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेने के अलावा, पुतिन दिल्ली में कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. इस दौरान कई अहम समझौते होने की संभावना है, जो भारत की क्षमता और रूस से संबंधों को नया आयाम दे सकते हैं।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर बैठक में भारत-रूस के समग्र रक्षा संबंधों की समीक्षा होने की संभावना है, पूरा जोर दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और विस्तार देने पर रहेगा।

भारत, रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप खरीदने पर

- सुखोई 30 के आधुनिकीकरण और सुखोई 57 के भारत में निर्माण पर भी फोकस रहेगा।

विचार कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये काफी प्रभावी साबित हुए थे. भारत ने एस-400 की 5 यूनिट खरीदने के लिए अक्टूबर 2018 में 5 अरब डॉलर का समझौता किया था, जिसकी 3 स्क्वाड्न मिल चुकी हैं।

भारत रूस से नई पीढ़ी के एस-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर सकता है. इसकी रेंज एस-400 के 400 किमी से 100-200 किमी अधिक है. ये अंतरिक्ष में 180-200 किमी ऊपर तक लक्ष्यों को भी भेद सकता है। भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक खेप खरीदने की प्रक्रिया में है. दसॉ एविएशन का राफेल, लॉकहीड मार्टिन का एफ-21, बोइंग का एफ/ए-18 और यूरोफाइटर टाइफून मुख्य दावेदार हैं. पुतिन के दौरे में रूस के सुखोई-57 फाइटर जेट की आपूर्ति की संभावना पर चर्चा हो सकती है. रूस इसकी 70 टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, मतलब बाद में भारत में इनका प्रोडक्शन भी हो सकता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष आंद्रे बेलौसोव के बीच गुरुवार को वार्ता के दौरान रूसी सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान खरीदने पर भी चर्चा हो सकती है।

बातचीत के दौरान प्रमुख फोकस भारतीय वस्तुओं का रूस में निर्यात बढ़ाने पर भी होगा। भारत अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ाने पर बात कर सकता है. रूस का फोकस फूड, समुद्री उत्पाद, डिजिटल सर्विसेज और दवा आदि की खरीद बढ़ाने पर रह सकता है।

यूक्रेन युद्ध खत्म होने के कगार पर?

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए यूएस के कुछ प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं और कुछ को खारिज कर दिया है और रूस समझौते पर पहुंचने के लिए यूएस के वार्ताकारों से जितनी बार भी मिलना होगा, मिलने को तैयार है।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव बुधवार सुबह पुतिन और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत, स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर के बीच मॉस्को में हुई बातचीत के बाद बोल रहे थे, जिसके बाद क्रेमलिन के एक सहयोगी ने कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

पेसकोव ने बुधवार को रिपोर्टरों से कहा कि यह कहना गलत होगा कि पुतिन ने यूएस के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है, उन्होंने कहा कि यह बैठक उन पर पहली आमने-सामने की राय का आदान-प्रदान थी। पेस्कोव ने कहा कि पुतिन ने कुछ प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था और कुछ को सामान्य बातचीत प्रक्रिया में खारिज कर दिया था।

भारत राफेल एफ 5 खरीदेगा?

पेरिस, 3 दिसम्बर। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि भारत 90 राफेल 4 फाइटर जेट खरीदने का प्लान बना रहा है। इनमें एफ 24 राफेल एफ 5 का एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है। यह खुलासा फ्रांस के विदेश मंत्रालय की एक एनालिसिस में आया है, बाद इस

- फ्रांस ने पुष्टि की है कि भारत ने 90 राफेल एफ 4 तथा 24 राफेल एफ 5 खरीदने का ऑर्डर दिया है, हालांकि, बाद में मंत्रालय ने यह लाइन वेबसाइट से हटा दी।

बात को पब्लिक एक्सेस से हटा दिया गया। इस एनालिसिस में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल के कथित नुकसान को लेकर चीनी मिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में बताया गया था, जिसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में फैलाया।

मुस्लिम महिला के तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा तलाक होने पर मुस्लिम महिला को दहेज में मिला सोना, नकदी व अन्य सामान लौटाना होगा

नई दिल्ली , 3 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उसकी शादी के समय पिता द्वारा पति को दी गई नकदी और सोने के गहने वापस लेने का अधिकार है। यह अधिकार मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सुरक्षित है। इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया।

हाईकोर्ट ने तलाकशुदा महिला के उस दावे को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने शादी के समय पति को पिता द्वारा दिए गए 7 लाख रुपये और सोने के गहनों (30 भौरी) की मांग की थी। महिला की शादी 2005 में हुई थी, 2009 में अलगाव और 2011 में तलाक के बाद, उसने 1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत 17.67 लाख रुपये की वसूली की मांग की थी, जिसमें नकद और सोने के गहने शामिल थे।

हाईकोर्ट ने दावा खारिज कर दिया था, क्योंकि विवाह रजिस्टर (काजी) और महिला के पिता के बयान में मामूली असंगति पाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह रजिस्टर और काजी का बयान केवल संदेह के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह के समय दिए गए संपत्ति और गहने महिला के भविष्य की सुरक्षा के लिए

- सुप्रीम कोर्ट ने रौशनारा बेगम के तलाक के मामले में यह फैसला दिया। रौशनारा का 2005 में निकाह हुआ था व 2011 में तलाक उसने निकाह में दिया गया सामान वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
- महिला ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहा कि 1986 अधिनियम में तलाकशुदा को शादी के समय दिया गया सामान वापस लेने का पूरा अधिकार है।

हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 अधिनियम की धारा 3(1)(डी) के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला को वह सब संपत्ति वापस लेने का अधिकार है , जो शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद उसके रिश्तेदारों, दोस्तों, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दी गई हो। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यह कानून महिला का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है और इसे अनुच्छेद 21 के तहत महिला के मानव अधिकार और आत्मनिर्णय के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को मंजूरी देते हुए आदेश दिया कि पति सीधे महिला के बैंक खाते में राशि जमा करे, और यदि ऐसा न किया गया तो 9 वार्षिक ब्याज लगेगा.

रौशनारा बेगम का निकाह 2005 में हुआ था और 2011 में उनका तलाक हो गया था। निकाह के समय महिला के पिता ने दामाद को सात लाख रुपए और तीस ग्राम सोने के गहने दिए थे, जिसकी जानकारी निकाह रजिस्टर में दर्ज थी। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने काजी और महिला के पिता के बयानों में असंगति का हवाला देते हुए महिला का दावा खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि निकाह के समय मिले धन और गहनों का संबंध महिला की सुरक्षा और गरिमा से है। अदालत ने इस कानून की व्याख्या महिला के समानता और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों के आधार पर की।

सुप्रीम कोर्ट ने रौशनारा के पति को सात लाख रुपए और तीस ग्राम सोने का मूल्य सीधे महिला के बैंक खाते में जमा करने का आदेश सुनाया. आदेश का पालन न करने पर पति पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा और उसे अदालत में इसके अनुपालन का हलफनामा देना होगा।

बिहार विधानसभा की समितियों में कांग्रेस को नेतृत्व मिलने की संभावना

पटना , 3 दिसम्बर । विधानसभा की समितियों में भी राजद की हिस्सेदारी इस बार कम हो जानी है। इसका असली कारण सदन में संख्या बल है। इस बार पार्टी को दो समितियों में नेतृत्व मिलने की आशा है। उनमें से लोक लेखा समिति की अपेक्षा स्वाभाविक है, क्योंकि विधानसभा में राजद मुख्य विरोधी दल है।

सरकार मेहरबान हुई तो एक समिति की अध्यक्षता कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है। इस तरह महागठबंधन को तीन समितियों से ही संतोष करना होगा। पिछली बार कुल 10 समितियों में सभापति की भूमिका में महागठबंधन के विधायक रहे थे। उनमें से छह का नेतृत्व राजद ने किया था।

इस बार राजद के मात्र 25 विधायक हैं। अगर एक विधायक भी कम हुआ होता, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के दर्जा हेतु सरकार की कृपा अपेक्षित हो जाती। दो विधायक कम होने पर तो दावेदारी का कोई आधार भी नहीं बनता।

2010 में तो सदन में राजद की संख्या इस पद के लायक भी नहीं थी। उसके बाद से पार्टी के अब तक के इतिहास में इस बार दूसरी बड़ी पराजय हुई है। तब राजद के मात्र 22 विधायक थे।

विधानसभा में 20 से 25 समितियों का गठन होता है। बहरहाल, 25 विधायकों के बूते राजद को दो से अधिक समितियों में नेतृत्व मिलने की संभावना कम ही है। कांग्रेस के छह और वामदलों के तीन और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के एक विधायक के दम पर तीसरी समिति मिल सकती है।

लोक लेखा समिति का नेतृत्व विपक्ष को दिए जाने की विधायी परंपरा है, जिसका अब तक अनुपालन होता

- क्योंकि समितियों में राष्ट्रीय जनता दल की भागीदारी कम होने की संभावना
- राष्ट्रीय जनतादल के पास मात्र 25 विधायक है और उसे दो से ज्यादा समितियों का नेतृत्व नहीं मिल सकता है।

रहा है। पिछली बार भाई वीरेन्द्र ने इस समिति का नेतृत्व किया था, जो इस बार भी मनेर से विजयी रहे हैं।

इसके अलावा, राजद को पुस्तकालय, बिहार विरासत विकास, आंतरिक संसाधन व केंन्द्रीय सहायता, शून्यकाल और गैर-सरकारी संकल्प समिति का सभापतित्व मिला था।

गैर-सरकारी संकल्प समिति के सभापति तेजप्रताप यादव थे, जो इस बार राजद से अलग होकर अपने जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं।

असिस्टेंट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई के दौरान, अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने ने पेश होकर कहा कि अपडेटेड सिलेबस को गत 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था, लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च, 2025 ही थी।

कश्मीर में कड़ाके की ठंड

श्रीनगर, 3 दिसम्बर। कश्मीर में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घाटी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है।

श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 डिग्री कम दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.2 डिग्री कम है।

दक्षिण कश्मीर का शोपियां माइनस 5.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा।

भाजपा यूपी में महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है

ओ बी सी से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चर्चा में है

नई दिल्ली , 3 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के ऐलान को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसमें दलित, पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण नेता भी दावेदारी में हैं, लेकिन इसमें एक महिला नेता का नाम भी है, जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री निरंजन ज्योति है। ओबीसी वर्ग से आने वाली निरंजन ज्योति फतेहपुर से सांसद रही हैं। ब्राह्मण वर्ग से पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी शामिल हैं। जबकि ओबीसी की बात करें तो धर्मपाल सिंह, बीएल वर्मा का नाम उभरकर सामने आया है। वहीं दलित चेहरों में रामशंकर कठेरिया और विद्या सागर सोनकर का नाम चल रहा है।

1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव

- 58 साल की साध्वी हमीरपुर से हैं तथा 21 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। वे राम मंदिर आंदोलन में भी काफी सक्रिय थीं।

के पहले यूपी में महिला कार्ड खेलेगी। बिहार, झारखंड, हरियाणा से लेकर हर राज्य के विधानसभा चुनाव में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं।

58 साल की साध्वी निरंजन ज्योति यूपी के हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखती हैं। इंटरमीडिएट तक पढ़ीं निरंजन ज्योति ने 21 साल की उम्र में गुरुदीक्षा लेकर संन्यास ले लिया था। राम मंदिर आंदोलन, विहिप, दुर्गा वाहिनी में सक्रियता के बाद वो भाजपा में आई थीं, यूपी में वे महिला भगवा ब्रिगेड का अहम चेहरा बन सकती हैं। उमा भारती जैसी फायर ब्रांड नेता की कम सक्रियता को देखते हुए भाजपा का ये दांव काम कर सकता है। निषाद समुदाय की निरंजन ज्योति यूपी में गैर यादव जातियों के बीच भाजपा की पकड़ और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लखनऊ में मंगलवार को शीर्ष नेताओं की बैठक में मंथन हुआ था। इसमें संघ नेता अरुण कुमार, भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा, सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। दिल्ली में भी शीर्ष स्तर पर इस मामले में मंत्रणा हुई है।

एक डॉलर की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके बाद "टेपर टैंट्रम्स" वाले वर्षों में भी रुपये पर दबाव बना रहा, जब अमेरिकी फेडरल रिज़र्व अपनी ढीली (अत्यधिक सहूलियत वाली) मौद्रिक नीति को वापस सख्त करने की तैयारी कर रहा था, ताकि डॉलर मजबूत रहे, और बाद में उसने डॉलर बाज़ार में की जाने वाली बड़ी पैमाने की फंड आपूर्ति को धीरे-धीरे कम करना शुरु कर दिया।

उस समय (टेपर टैंट्रम्स वाले दिनों में) रुपये का मूल्य 50 रुपये प्रति डॉलर से गिरकर 60 रुपये प्रति डॉलर से ऊपर चला गया था।

अब एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर ऊँचे शुल्क लगा दिए हैं। इन शुल्कों से भारतीय सामान अमेरिकी बाज़ार में महँगा हो गया है और अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गया है। असल में, सबसे बड़े मार्केट में से एक, अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात घट गया है, इसका मतलब है कि भारत को पहले की तुलना में कम डॉलर मिल रहे हैं। अत: विदेशी इन्स्टिट्यूशनल इन्वैस्टर्स भारत से अपने फंड निकाल रहे हैं औरउसे डॉलर में बदलकर बाहर भेज रहे हैं, इसलिए देश में डॉलर का प्रवाह घट गया है।

बाज़ार की इन गतिविधियों के अलावा कुछ बुनियादी कारण भी काम कर रहे हैं। कुछ अनुभवी बाज़ार विश्लेषकों ने इन पर ध्यान दिलाया है। भारत में महंगाई 5 प्रतिशत से अधिक है, जबकि कई बड़े देशों में यह 2 प्रतिशत से कम है। यह अंतर रुपये पर असर डालता है।

कुछ विशेषज्ञों ने भारत और अन्य देशों की उत्पादकता पर भी ध्यान दिलाया है। यानी एक इकाई संसाधन से भारत में श्रमिक विदेशों की तुलना में कम उत्पादन करते हैं। इससे हमारी दक्षता कम होती है और हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता पर असर पड़ता है।

इन सभी कारणों के चलते रुपये का मूल्य नीचे जा रहा है। लेकिन फिलहाल रुपये की अचानक तेज़ गिरावट की सबसे बड़ी वजह एफआईआई द्वारा भारतीय शेयर बाज़ारों में भारी बिक्री और उसके बाद अमेरिका जैसे ज्यादा लाभ वाले बाज़ारों में पैसा भेजना है।

हल्द्वानी में भारी सुरक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, यह नहीं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास बहती है। दिसंबर 2022 में, कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया था कि वह निवासियों को क्षेत्र खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दे, और इसके बाद "आवश्यकता के अनुसार बल का उपयोग करके अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करें।"

हालांकि, इसके बाद भारी अफरा-तफरी मच गई, जिसके कारण क्षेत्र में भारी प्रदर्शन हुआ जो क्षेत्र में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक था। एक अपील के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पर रोक लगा दी, यह टिप्पणी करते हुए कि 50,000 लोगों को एक ही रात में कैसे बेदखल किया जा सकता है।

पहले की रिपोर्टों के अनुसार, 2016-17 में रेलवे और जिला प्रशासन के एक संयुक्त सर्वे में 4,365 अवैध कब्जों की पहचान की गई थी।

मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की आशंका में, 400 से अधिक पुलिस अधिकारी और के कर्मी तैनात किए गए थे। नैनीताल के एसएसपी मन्जुनाथ टी. सी. ने कहा कि

- मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और देखना है कि वहां से फैसला किसके पक्ष में आता है।

अगर स्थिति तनावपूर्ण होती है तो पैरामिलिट्री बल भी तैनात किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट रेलवे ज़मीन पर कब्जे के मामले में निर्णय देगा, और हम फैसले के लिए तैयार हैं। पूरे बनभूलपुरा को घेर लिया गया है और चार ज़ोन में बांटा गया है। हमने तीन एसपी, चार सीओ, आठ इंस्पेक्टर, आठ एस एच ओ, 400 अधिकारी, और पी ए सी की दो कंपनियां, फायरिंग और टियरगैस स्कॉड, एंटी-रायट फोर्स, फायर यूनिट्स और ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया है। हम आई टी बी पी तथा सी आर पी एफ जैसे पैरामिलिट्री बलों को भी तैयार रखे हुए हैं। पुलिस किसी भी प्रकार की गतिविधि पर कार्रवाई करेगी, जो फैसले के कारण उत्पन्न हो।"

नैनीताल पुलिस ने चेतावनी दी है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ "कठोरतम कार्रवाई" की जाएगी। जिला सीमा पर गहन जांच की निर्देश दी गई है, संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, "संदिग्ध" व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, और सोशल मीडिया पर करीबी निगरानी रखी जा रही है।

जहाँ तीन कालोनियां गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर - के निवासी यह दावा करते हैं कि वे कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, वहीं रेलवे ने पहले कहा था कि 1959 की एक अधिसूचना, 1971 के राजस्व रिकॉर्ड और 2017 के सर्वेक्षण के परिणाम ज़मीन पर उनके मालिकाना हक को प्रमाणित करते हैं।

यह क्षेत्र 2.2 किलोमीटर लम्बी ज़मीन पर फैला हुआ है, और यहाँ कम से कम तीन सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, 10 मस्जिदें, 12 मदरसे, एक सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और एक मंदिर स्थित है।

दवा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य के साथ केंद्र सरकार के अधिकारियों तक पहुंचेगी. इससे तुरंत जांच शुरू हो सकेगी और संबंधित जिले के औषधि नियंत्रक अधिकारी को 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्यों को आदेश जारी करते हुए सभी दवा दुकानों पर क्यूआर कोड और हेल्पलाइन नंबर तत्काल चस्पा करने के लिए कहा है।

ये सूचना दुकानों पर ऐसी जगह चस्पा करनी होगी, जो हर किसी को दिख सके. राज्यों से यह जानकारी मांगी गई है कि कितनी दुकानों में नया नियम लागू किया गया है, उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर कोई दुकानदार कोड को छिपाकर रखता है, काउंटर के अंदर रखता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।

आदेश में राज्यों के ड्रग इंस्पेक्टरों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी दुकानदार इसका पालन करें।

एक बार फिर ...

- मोदी समर्थकों ने भी प्रत्युत्तर में "चाय पे चर्चा" कार्यक्रम चलाया, तथा विडियो लिंक के मार्फत देश के चाय की थड़ी पर, लोगों से मोदी की बात कराने का लोकप्रिय कार्यक्रम चलाया।
- हाल ही में बिहार कांग्रेस ने एक एआई निर्मित विडियो चलाया था, जिसमें मोदी को सपने में उनकी मां डाटते हुए दिखीं तथा वे मोदी का राजनीति से अपनी नाखुशी जाहिर कर रही हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाय बेचने वाली पृष्ठभूमि का मज़ाक उड़ाया है, अब तक 150 बार उन्हें अपमानित किया है और बिहार में तो उनकी माँ तक को निशाना बनाया।"

हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी खुद सोनिया गांधी को "जर्सी गाय" कह चुके हैं और कई विपक्षी नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणियाँ करते रहे हैं, फिर भी कांग्रेस द्वारा की गई प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी अक्सर राजनीतिक तौर पर उलटी पड़ी है। वर्ष 2014 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और कांग्रेस के मंच पर चाय परोस सकते हैं। राहुल गांधी ने उस बयान से असहमति भले ही जता दी थी, लेकिन इस टिप्पणी ने कांग्रेस के अभियान को नुकसान पहुँचाया था। भाजपा रणनीतिकारों ने "चाय पे चर्चा" का देशव्यापी अभियान चलाया, जिसमें मोदी ने सैकड़ों जगहों के चाय स्टॉलों से वीडियो लिंक के ज़रिए मतदाताओं से बातचीत की थी।

हाल ही में बिहार कांग्रेस इकाई ने एक एआई वीडियो साझा किया था, जिसमें दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को सोते समय मां सपने में दिख रही हैं और उनकी आलोचना कर रही हैं। इस घटना से कांग्रेस या महागठबंधन को हाल ही में खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनावों में कोई फायदा नहीं मिला।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908